डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

किसान कल्याण वर्ष-2026
समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 फरवरी, 2026, डिस्पेच दिनांक 1 फरवरी, 2026

| वर्ष 69 | अंक 17 | भोपाल | 1 फरवरी, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

77वें गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की ली सलामी, प्रदेश की प्रगति का रखा विस्तृत विज़न

भोपाल, प्रदेश में 77वाँ गणतंत्र दिवस अत्यंत गरिमा, हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्रीडॉ. मोहन यादवने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड, शिप्रा तट स्थित सुनहरी घाट पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तथा विभागीय झांकियों को भी पुरस्कृत किया। समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद श्री बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएँ एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिप्रा तट पर तिरंगे रंग के गुब्बारे आकाश में छोड़कर राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश दिया। इस दौरान मां शिप्रा में तिरंगे रंग से सजी नावों पर तिरंगा ध्वज थामे होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के जवान देशभक्ति गीत गाते हुए नजर आए। घाट को तिरंगे की थीम पर सजाया गया था और जनजातीय भील कलाकारों द्वारा भगोरिया नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और भारत के प्रति गर्व का भाव और अधिक सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व-गुणों के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा निरंतर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए ही इस वर्ष गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन पावन शिप्रा तट पर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के "गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" के विकास के आह्वान को केंद्र में रखकर संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण के चार प्रमुख मिशन प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 को प्रदेश में "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2002-03 में जहाँ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का बजट मात्र 600 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2024-25 में इसे बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" की दिशा में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया तथा 1360 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना के अंतर्गत 1300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान हैं, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रदेश में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से कानूनों को सरल बनाया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मध्यप्रदेश की सहभागिता से निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक प्रगति हुई है और मध्यप्रदेश अब विद्युत के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर बन चुका है। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 9508 मेगावॉट हो गई है तथा 30 लाख विद्युत पम्पों को सोलर पम्प में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही वर्ष में इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। द्वितीय चरण में जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उज्जैन में प्रदेश का दसवाँ एयरपोर्ट बनेगा और शहर को मेडिसिटी के रूप में नई पहचान मिलेगी। प्रदेश में जल्द ही शासकीय बस सेवाओं का संचालन भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी।

शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शाला स्तर पर ड्रॉप-आउट दर 6 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। सांस्कृतिक अभ्युदय के क्षेत्र में भी प्रदेश ने विशिष्ट पहचान बनाई है और प्रदेश के 15 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की प्रगति की इमारत में सुशासन नींव का पत्थर है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि अभ्युदय मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए सभी नागरिक मिलकर कार्य करें और राज्य की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश निरंतर प्रगति करते हुए राष्ट्र के गौरव को और अधिक ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आगामी कार्ययोजना पर दिए विस्तृत निर्देश

सीपीपीपी मॉडल के माध्यम से सहकारिता संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से सशक्त बनाने के निर्देश

माह के अंत तक शत-प्रतिशत पैक्स को ई-पैक्स में परिवर्तित करने पर विशेष जोर

भोपाल :सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपेक्स बैंक में सहकारिता विभाग के संभागों में पदस्थ संयुक्त आयुक्तों एवं जिलों में पदस्थ उप एवं सहायक आयुक्तों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभाग की वर्तमान स्थिति, प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (उपभोक्ता संघ) श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक (बीज संघ) श्री महेंद्र दीक्षित, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ई-पैक्स एवं पोर्टल आधारित अंकेक्षण की गहन समीक्षा

बैठक के दौरान ई-पैक्स / पोर्टल आधारित अंकेक्षण, अंकेक्षण की वर्तमान प्रगति, पैक्स पुनर्गठन, सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति एवं प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री सारंग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि माह के अंत तक प्रदेश की सभी पैक्स को शत-प्रतिशत ई-पैक्स में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-पैक्स व्यवस्था से पारदर्शिता और गति आएगी तथा किसानों एवं सदस्यों को समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध होंगी। जिलों में आई.टी. सेल, नवाचार सेल एवं सीपीपीपी सेल के गठन को लेकर उन्होंने निर्देश दिये कि ये सभी विशेष प्रकोष्ठ अत्यंत सक्रिय रहें, इनके कार्यों की पाक्षिक समीक्षा की जाए तथा रिपोर्ट उच्च स्तर पर प्रस्तुत की जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर निगरानी बनी रहे।

सीपीपीपी मॉडल पर करें ठोस और परिणामोन्मुख कार्य

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि समस्त मैदानी अधिकारी सीपीपीपी मॉडल को व्यवहार में लाकर सहकारिता संस्थाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और व्यवसायिक रूप से सक्षम बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संयुक्त आयुक्त संभाग स्तर पर प्रतिष्ठित एवं सफल व्यवसायियों के साथ बैठकें आयोजित करें तथा सीपीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओडीओपी (एक जिला–एक उत्पाद) के चयनित उत्पादों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त पैक्स के साथ-साथ जिला सहकारी संघों, जिला थोक भंडारों, मार्केटिंग सोसायटियों एवं नवाचार के अंतर्गत गठित सहकारी संस्थाओं को सक्रिय करने के लिए स्पष्ट, समयबद्ध एवं व्यावहारिक कार्य योजनाएँ तैयार करें।

ई-पैक्स के सफल क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन पर विशेष ध्यान

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि ई-पैक्स के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित एवं तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कंप्यूटर दक्ष कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मानव संसाधन की कमी को शीघ्र दूर किया जाए। आवश्यक पदों पर भर्ती प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रारंभ की जाए। नियुक्त कर्मचारियों को ई-पैक्स प्रणाली का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए।

सहकारिता को डिजिटल और नवाचारी स्वरूप देने का संकल्प

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता विभाग को डिजिटल, नवाचारी एवं पारदर्शी व्यवस्था के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन लक्ष्य आधारित, समयबद्ध एवं परिणामोन्मुख तरीके से किया जाए, ताकि सहकारिता संस्थाएँ सशक्त हों और किसानों, उपभोक्ताओं तथा आम नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो।

प्रभारी मंत्री श्री सारंग के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

विभागीय झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुति बनीं आकर्षण का केंद्र

मंत्री श्री सारंग मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में हुए शामिल

खरगोन : मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से डीआरपी लाईन में किया गया। प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया, जिसमें राज्य शासन की कृषि, औद्योगिक और अधोसंरचना विकास, सांस्कृतिक अभ्युदय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उड्डयन, सहकारिता, खेलकूद, स्वच्छता, वित्तीय प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, श्रमिक कल्याण, जनजातीय वर्ग और वृद्धजन कल्याण जैसे क्षेत्रों की उपलब्धियों तथा सुशासन व्यवस्था अंतर्गत विभिन्न नवाचारों का उल्लेख किया गया।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री द्वारा रंगीन गुब्बारे छोड़े गए जिसके बाद परेड द्वारा हर्ष फायर कर राष्ट्रपति की जयघोष की गई। परेड कमांडर सूबेदार श्री मुकेश हायरी और सहायक परेड कमांडर सूबेदार श्री दीपेंद्र स्वर्णकार के नेतृत्व में एसएएफ, महिला पुलिस बल, जिला पुलिस बल, होमगार्ड, वनविभाग, एनसीसी, स्काउट्स और गाइड तथा शौर्या दल ने शानदार मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मंत्री श्री सारंग ने परेड कमांडरों का परिचय प्राप्त किया और कारगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। लखपति दीदियों की आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार और कृषि और उद्यानिकी विभागों की संयुक्त झांकी को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है, जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा नवाचारों से किसानों का उद्धार प्रदर्शित किया गया। नगर पालिका परिषद खरगोन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता जन जागरूकता पर आधारित झांकी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में आठ अन्य विभागों की झांकियों ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम में बीकेजी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया गया। माता शबरी शिक्षा परिसर, सेंट ज्यूद हायर सेकेंडरी स्कूल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आदित्य विद्या विहार, अविसंस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री सारंग ने उत्कृष्ट कार्य के लिए शासकीय सेवकों को प्रशस्ति पत्र और परेड प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सर्वोत्तम परेड के लिए एनसीसी सीनियर गर्ल्स, वन विभाग और शौर्या दल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

कार्यक्रम में विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार, श्री राजकुमार मेव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुबाई तंवर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, डीएटीसीसी सदस्य श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल, निमाड़ रेंज पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र वर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, सहायक कलेक्टर श्री जमादार फरहान इरफान सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश में बनेगी पहली सहकारी क्षेत्र की अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला

आम उपभोक्ता भी करा सकेंगे दूध व दुग्ध उत्पादों की जांच

नेशनल डेयरी प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट अंतर्गत किया जा रहा है प्रयोगशाला का निर्माण

भोपाल :प्रदेश में पहली सहकारी क्षेत्र की अत्याधुनिक केन्द्रीय राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में स्थापित की जा रही है, जिसका अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह प्रयोगशाला केन्द्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल में सहकारिता क्षेत्र की यह पहली राज्य स्तरीय प्रयोगशाला होगी।

राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला में आम उपभोक्ता भी दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगे। यदि आपके घर में आने वाले दूध या उससे बने उत्पादों में मिलावट की आशंका है, तो अब जांच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जहां आम उपभोक्ता के साथ देश एवं प्रदेश की खाद्य उत्पादक संस्थाएं भी दूध और दुग्ध उत्पादों का परीक्षण करा सकेंगी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाला दूध एवं दुग्ध उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रदेश में अब तक दूध एवं दुग्ध उत्पादों की जांच एक बड़ी चुनौती रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

यह प्रयोगशाला केंद्र शासन के मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहयोग से स्थापित की जा रही है, जिसे (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज) तथा (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) से मान्यता प्राप्त होगी।

प्रयोगशाला के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ 40 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक सात मशीनों की खरीदी पूरी हो चुकी है, जबकि शेष मशीनों, केमिकल्स एवं ग्लासवेयर की खरीदी प्रक्रिया जारी है। शीघ्र ही दूध एवं दुग्ध पदार्थों के परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थों की 100 से अधिक मानकों पर जांच की जाएगी। इसमें पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, हेवी मेटल्स, अफ्लाटॉक्सिन, वसा की शुद्धता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ यूरिया, आयोडीन, माल्टोज, शुगर, नमक एवं अन्य प्रकार की मिलावटों की जांच शामिल होगी।

इस प्रयोगशाला की सुविधा आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ देश की विभिन्न खाद्य उत्पादक संस्थाओं को भी उपलब्ध होगी। इसके स्थापित होने से दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, शुद्धता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और प्रदेश के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रदेश में सहकारिता का नया प्रयोग है सी-ट्रिपल-पी : प्रभारी मंत्री श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग ने किया सहकारी प्रेरणा सदन का लोकार्पण

खरगोन, मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को मजबूती देने के उद्देश्य से केंद्र शासन में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की तथा केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन और ऋण जैसे क्षेत्रों में सहकारिता को जमीन पर उतारने का काम कर रहे है। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि सी-ट्रिपल-पी CPPP के माध्यम से सहकारिता-सार्वजनिक-निजी-भागीदारी का नया प्रयोग किया जा रहा है, जिससे व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में सशक्त योगदान देने के लिए जिलेवासियों और सहकारिता आंदोलन से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई दी। श्री सारंग ने ये विचार सहकारी प्रेरणा सदन के लोकार्पण समारोह के दौरान व्यक्त किए।

प्रभारी मंत्री श्री सारंग के मुख्य आतिथ्य में रविन्द्र नगर स्थित जिला सहकारी संघ द्वारा नवनिर्मित सहकारी प्रेरणा सदन का लोकार्पण किया गया। यह भवन पूर्णतः स्वयं की निधि से निर्मित आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

इस अवसर पर विधायक श्री बालकृष्ण पाटीदार, श्री राजकुमार मेव, डीएटीसीसी सदस्य श्रीमती नंदा ब्राह्मणे, कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक श्री रविंद्र वर्मा, संयुक्त पंजीयक श्री अमरीश वैद्य, उपायुक्त सहकारिता श्री कांशीराम अवासे सहित अन्य अधिकारीगण व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का चलाया जाएगा तीसरा चरण

पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख सचिव श्री उमराव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा की

भोपाल :पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली तथा पशुपालकों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन एंव डेयरी विभाग, म.प्र. गो संवर्धन बोर्ड व सांची बोर्ड के अधिकारियों ने कृषक कल्याण वर्ष-2026 में किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी।

प्रमुख सचिव श्री उमराव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी विकास से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से लागू किया जाए, जिससे पशुपालकों की आय में निरंतर वृद्धि हो सके। प्रदेश में पशुपालकों की आय बढ़ाने एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण जल्द ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान अंतर्गत दो चरणों में 12 लाख से अधिक पशुपालको के घर पहुंचकर सीधा संवाद किया गया। उन्हें पशुओं के नस्ल सुधार, पशु पोषण व पशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया।

तीसरे चरण में प्रदेश में 3 से 4 पशुओं का पालन करने वाले पशुपालकों से सीधा संवाद किया जाएगा। उन्हें भी पशुओं के नस्ल सुधार, पशु पोषण व पशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव ने स्वावलंबी गोशाला नीति 2025, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, डेयरी विस्तार, सहकारी समितियों के गठन के साथ ही मुर्गीपालन, बकरी पालन के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा की।

बैठक में संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉ. पी.एस. पटेल, सांची बोर्ड के एमडी डॉ. संजय गोवानी, ग्रुप हेड श्री असिम निगम, अतिरिक्त उपसंचालक डॉ. अनुपम अग्रवाल, मप्र गोसंवर्धन बोर्ड सहित किसान संगठन के प्रतिनिधि, नाबार्ड, विभागीय संगठनों के प्रतिनिधिगण सहित गोशाला संचालक उपस्थित रहे।

पशुपालन एवं डेयरी प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि प्रदेश के कई ग्रामों में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयासों से नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं, जिससे पशुपालक उन्नत नस्ल का पशुपालन कर अधिक दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ग्रामों को आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा अन्य ग्रामों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश में क्षीरधारा ग्राम योजना शुरू की गई है। यह तीन चरणों में संचालित होगी। पहले चरण में प्रदेश के 5 हजार से अधिक गांवों को चुना गया है।

किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार : केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नए 'सीड एक्ट' की दी जानकारी

नकली बीजों पर होगी सख्त कार्रवाई, परंपरागत बीज प्रणाली बनी रहेगी सुरक्षित- श्री शिवराज सिंह

नकली बीज की समस्या से किसानों को मिलेगी पूरी राहत- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

अब घटिया बीज बेचने वालों को 30 लाख रुपए तक जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान प्रस्तावित - श्री शिवराज सिंह

ट्रेसिबिलिटी लागू होते ही नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी, ट्रेसिबिलिटी सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता- श्री शिवराज सिंह

हर सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कोई भी अनधिकृत विक्रेता बीज नहीं बेच पाएगा- श्री शिवराज सिंह

दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए नए सीड एक्ट (Seed Act 2026) की विशेषताओं और उसके किसानों पर होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कदम है।

"हर बीज की पूरी कहानी अब किसानों तक पहुँचेगी"

मीडिया के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Trace-ability) की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया, "हमने कोशिश की है कि ऐसा सिस्टम बने, जिसमें यह पूरा पता चल सके कि बीज कहां उत्पादित हुआ, किस डीलर ने दिया और किसने बेचा।" हर बीज पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही किसान यह जान सकेगा कि वह बीज कहां से आया है। इससे घटिया या नकली बीज न केवल रोके जा सकेंगे बल्कि यदि वे बाजार में आएंगे भी तो जिम्मेदार व्यक्ति पर शीघ्र कार्रवाई संभव होगी।

"अब घटिया बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं"

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी। उन्होंने कहा, "खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे। जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा।" इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

"बीज कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य"

श्री चौहान ने कहा कि अब हर सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे यह साफ रहेगा कि कौन सी कंपनी अधिकृत है। उन्होंने कहा, "पंजीकृत कंपनियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी और कोई भी अनधिकृत विक्रेता बीज नहीं बेच पाएगा।" इससे बाजार में फर्जी कंपनियाँ खत्म होंगी और किसानों को सही स्रोत का बीज मिलेगा।

"परंपरागत बीजों पर कोई पाबंदी नहीं"

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने इस भ्रम को दूर किया कि नया कानून किसानों के परंपरागत बीजों पर रोक लगाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा, "किसान अपने बीज बो सकते हैं, दूसरे किसान को बीज दे सकते हैं। स्थानीय स्तर पर जो परंपरागत बीज विनिमय की परंपरा है, वो जारी रहेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।" उन्होंने उदाहरण दिया कि ग्रामीण इलाकों में बोनी के समय किसान आपस में बीज लेते–देते हैं और बाद में उसे सवा गुना वापिस कर देते हैं, यह पारंपरिक प्रणाली आगे भी जारी रहेगी।

"अब घटिया बीज बेचने वालों को 30 लाख तक जुर्माना और सजा"

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री चौहान ने कहा, "अभी तक 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब प्रस्ताव है कि 30 लाख रुपये तक जुर्माना हो और अगर कोई जानबूझकर अपराध करता है तो सजा का भी प्रावधान है।" उन्होंने कहा कि सब कंपनियां खराब नहीं हैं, लेकिन जो किसान को धोखा देंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

"ICAR और देसी कंपनियां रहेंगी मैदान में मजबूत"

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सीड एक्ट में तीनों स्तर पर प्रावधान किए गए हैं- सार्वजनिक क्षेत्र (ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, KVKs), देसी कंपनियां जो उच्च गुणवत्ता के बीज बनाती हैं, विदेशी बीजों के लिए उचित मूल्यांकन व्यवस्था।उन्होंने कहा, "विदेश

से आने वाले बीज पूरी तरह जांच और मूल्यांकन के बाद ही स्वीकृत होंगे। हमारे सार्वजनिक और देसी निजी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा ताकि किसानों तक अच्छे बीज पहुंचें।"

"किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान"

किसानों में अवेयरनेस की कमी पर पूछे गए सवाल पर श्री चौहान ने कहा, "हमने 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' जैसे प्रयास शुरू किए हैं ताकि वैज्ञानिक, अधिकारी और प्रगतिशील किसान गांवों तक जाकर किसानों को अवेयर कर सकें।" उन्होंने बताया कि देश के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) किसानों को बीजों की गुणवत्ता, बीज चयन और शिकायत निवारण की जानकारी देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

"नकली बीज बेचने वालों पर सख्त सजा"

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि अब यदि कोई जानबूझकर घटिया बीज तैयार करेगा या बेचेगा, तो उसके खिलाफ 3 साल तक की जेल और 30 लाख तक का जुर्माना संभव है। उन्होंने कहा, "पहले यह मामला कमजोर था, अब हम इसे प्रभावी बना रहे हैं ताकि किसान को न्याय मिले।"

"1966 का पुराना कानून अब होगा आधुनिक"

उन्होंने कहा कि 1966 का सीड एक्ट पुराने समय का था जब न तकनीक थी न डेटा। अब हम एक आधुनिक कानून ला रहे हैं, जो ट्रेसिबिलिटी, डिजिटल रिकॉर्ड और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित है ताकि भविष्य में कोई भी किसान ठगा न जाए।

"राज्य सरकारों के अधिकार रहेंगे यथावत"

इस सवाल पर कि कुछ लोगों ने यह आशंका जताई थी कि नया कानून राज्यों के अधिकार घटा देगा, इस पर कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने साफ कहा, "कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारों के अधिकार वैसे ही बने रहेंगे। केंद्र केवल समन्वय करेगा और राज्यों के सहयोग से यह कानून लागू होगा।"

"हमारा लक्ष्य- हर किसान को सही बीज"

श्री चौहान ने कहा, "हमारा उद्देश्य है कि हर किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज मिले। अच्छी कंपनियों को प्रोत्साहन और गलत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, यही इस कानून का सार है।" उन्होंने कहा कि सीड एक्ट 2026 के माध्यम से सरकार हर किसान को सुरक्षित, भरोसेमंद और उत्पादक बीज उपलब्ध कराने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठा रही है।

डीडीएम नाबार्ड व मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति में सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

छतरपुर, मध्यप्रदेश डीडीएम नाबार्ड एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति मेंनाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण योजनान्तर्गत पैक्स कर्मचारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 14 जनवरी 2026 को सहकारी प्रशिक्षण केंद्र नौगांव द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय टेकारी, छतरपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारामां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके पश्चात सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों, राष्ट्रीय सहकारिता नीति–2025 एवं मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम– 2023 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पैक्स की भूमिका, बैंकिंग प्रणाली से समन्वय तथा सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर बल दिया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (DDM)द्वारा नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं, सॉफ्टकॉब प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं सहकारी क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों, फसल उत्पादकता बढ़ाने, कम लागत में अधिक उत्पादन, उर्वरक एवं कीटनाशकों के वैज्ञानिक उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही पैक्स के कम्प्यूटरीकरण, ई-पैक्स प्रणाली, नवीन बायलॉज एवं डिजिटल लेन-देन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का संचालनजिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। पैक्स कर्मचारियों एवं प्रबंधकों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताते हुए आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की विभिन्न पैक्स से पैक्स प्रबंधक एवं कर्मचारीउपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

हर खेत तक पहुंचाएंगे पानी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मंत्रि-परिषद् ने राजगढ़ एवं रायसेन जिले की तीन सिंचाई परियोजनाओं को दी मंजूरी

सारंगपुर, भोजपुर और उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताकर किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को किया संबोधित

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान हमारा अभिमान हैं। किसानों का मान बढ़ाने हमने कोई कमी नहीं की। प्यासे खेतों तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और हर खेत तक पानी पहुंचाकर हम यह लक्ष्य जल्द ही पाकर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में किसानों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए संकल्पित है। प्रदेश के किसान समृद्ध और सशक्त बनें, इसी मंशा से हमने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना, केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और ताप्ती ग्राउंड वॉटर रिचार्ज मेगा परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इन तीनों नदी परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रदेश का लगभग सम्पूर्ण कृषि रकबा सिंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी मध्यप्रदेश में कृषि का सिंचित रकबा 56 लाख हेक्टेयर है। हमारी सरकार ने इसे जल्द से जल्द 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के एक-एक गांव और हर एक खेत तक बिजली और पानी की सतत् आपूर्ति बरकरार रहे, यही हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र और रायसेन जिले की भोजपुर एवं उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं किसानों ने आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार जताया। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी, 2026 को हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में राज्य सरकार द्वारा इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के किसानों के हित में करीब 900 करोड़ रुपए लागत वाली तीन अलग-अलग सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसान इसी सौगात के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री निवास आए थे। बड़ी संख्या में आए किसानों ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आल्हादित होकर अभिनंदन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान शिव की प्रतिमा, बीजासन माता का चित्र, जैविक अनाज एवं स्टील और लकड़ी के हल की प्रतिकृति भेंटकर अपना हर्ष और आभार जताया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं एक किसान परिवार से आते हैं और खेती के लिए सिंचाई का महत्व उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, क्षिप्रा जैसे अनेक नदियों का मायका है और इन्हीं के कारण हमारा प्रदेश जल संपदा से संपन्न है। प्रदेश में बहती नदियां किसानों को सिंचाई के जल उपलब्ध कराती हैं, ये नदियां हमारे लिए जीवन रेखा के समान हैं। कृषि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के विकास में हम कोई कसर रख रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री सुंदरलाल पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश में किसानों के कल्याण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए स्मरण किया। उन्होंने कहा कि स्व. श्री पटवा प्रदेश के एक आदर्श राजनेता थे।

इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के किसान होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा राजगढ़ एवं रायसेन जिले की कुल 898.42 करोड़ रूपये लागत वाली तीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए की स्वीकृति दी गई है। राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में 396 करोड़ 21 लाख रूपये लागत वाली मोहनपुरा विस्तारीकरण (सारंगपुर) सिंचाई परियोजना से सारंगपुर तहसील के 26 ग्रामों की 11,040 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। इस परियोजना से 10 हजार 400 किसान परिवार लाभांवित होंगे। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में 115 करोड़ 99 लाख रूपये लागत वाली सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना से सुल्तानपुर तहसील के 20 गांवों की 5,700 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी। इससे 3,100 किसान परिवारों को लाभ होगा। साथ ही रायसेन जिले की ही उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र की 386 करोड़ 22 लाख रुपये लागत वाली बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना से बरेली तहसील के 36 गांवों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस परियोजना से 6,800 किसान परिवार सीधे तौर पर लाभांवित होंगे।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक

किसान निर्धारित समय पर करायें पंजीयन : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

भोपाल : रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 7 फरवरी से 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है।

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। पूर्व वर्षों की किसी अपात्र संस्था में केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में पंजीयन के लिए नहीं रखा जायेगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक का नाम खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें।

सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें। इस कार्य के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरीफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस

विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएँ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में 77वाँ गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

भोपाल। प्रदेशभर में 77वाँ गणतंत्र दिवस अत्यंत गरिमामय, अनुशासित एवं देशभक्ति से ओत-प्रोत वातावरण में मनाया गया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रेरक संबोधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

राज्य सहकारी संघ, भोपाल में गरिमामय समारोह

भोपाल स्थित राज्य सहकारी संघ कार्यालय परिसर में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण पश्चात अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों का स्मरण कराता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों सेसंविधान के प्रति निष्ठावान रहते हुए देश की एकता, अखंडता एवं सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करनेका आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि "सहकार से समृद्धि" का संकल्प तभी साकार होगा जब सभी सहकारी संस्थाएँ पारदर्शिता, ईमानदारी एवं व्यावसायिक दक्षता के साथ कार्य करें।

इंटर्नशिप अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र वितरण

कार्यक्रम के दौरान इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रबंध संचालक महोदय द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री संजय सिंह एवं प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल श्री गणेश प्रसाद मांझी उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण देशभक्ति गीत ने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों को देश प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया। इस अवसर पर श्री अरुण कुमार जोशी, श्री पी.के. परिहार, श्री संतोष येडे, श्री रॉबिन सक्सेना, सीड संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष सिंह राजपूत सहित CHCDS परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागी उपस्थित रहे। साथ ही गांधी शिल्प बाजार में सहभागिता कर रहे समस्त शिल्पकारों ने भी समारोह में भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में प्राचार्य श्री दिलीप मरमट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण पश्चात केन्द्र के समस्त कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया।

अपने संबोधन में प्राचार्य महोदय ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को संविधान के मूल्यों के अनुरूप कार्य करने का संदेश देते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ दीं।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर में प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान का सामूहिक गायन किया गया। प्राचार्य महोदय ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान निर्माताओं के योगदान को स्मरण करते हुए सभी को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संदेश दिया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, नौगांव में 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केन्द्र का समस्त स्टाफ एवं पूर्व कर्मचारियों के सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया, इसके पश्चात ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का आयोजन हुआ।

इस अवसर पर प्रशिक्षक श्री हृदेश कुमार ने गणतंत्र दिवस के महत्व एवं शहीदों के अमर बलिदान पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगीत ने वातावरण को देशभक्ति से भर दिया। इसके पश्चात श्री खूबचंद नाई (प्रभारी लिपिक) ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

अपेक्स बैंक भोपाल में 77वाँ गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया

भोपाल। अपेक्स बैंक, भोपाल में 77वाँ गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास, अनुशासन एवं देश भक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपेक्स बैंक मुख्यालय, तात्या टोपे नगर स्थित प्रांगण में एक गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्य प्रदेश श्री मनोज पुष्प तथा अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ दी गईं। समारोह के दौरान परिसर राष्ट्रभक्ति एवं उत्साह से ओत-प्रोत दिखाई दिया।

इस अवसर पर उप सचिव सहकारिता श्री मनोज सिन्हा, प्राचार्य ट्रेनिंग कॉलेज श्री पी.एस. तिवारी, वि.क.अ. श्रीमती अरुणा दुबे, श्री अरुण मिश्रा, श्री संजय मोहन भटनागर, आवास संघ के प्रबंध संचालक श्री आर.एस. विश्वकर्मा, उप महाप्रबंधक श्री के.टी. सज्जन सहित श्री अरविंद बौद्ध, श्री विवेक मलिक, श्री करूण यादव, श्री अजय देवड़ा, श्री आर.के. गंगेले, श्री एम.के. अहलाद, श्री एस.के. जैन तथा बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

ध्वजारोहण के उपरांत सभी उपस्थितजनों द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान का गायन किया गया। इसके पश्चात भारत माता की जय एवं गणतंत्र दिवस अमर रहे के नारों से सम्पूर्ण परिसर गूंज उठा।

एफपीओ हेतु क्षमता निर्माण पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

भोपाल। नाबार्ड की SOFTCOB योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के तत्वावधान में कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) के क्षमता निर्माण विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 20 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एफपीओ के पदाधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) एवं लेखापालों को संगठनात्मक, वित्तीय, प्रबंधन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना रहा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्री अरुण कुमार जोशी, श्री पी.के. परिहार, सीबीबीओ के विषय-विशेषज्ञ, तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। शुभारंभ सत्र में वक्ताओं ने एफपीओ की भूमिका को किसानों की आय वृद्धि, बाजार से जुड़ाव एवं सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

प्रथम दिवस प्रतिभागियों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, जिसके पश्चात बी-पैक्स एवं एफपीओ की बुनियादी अवधारणा पर चर्चा की गई। श्री पी.के. परिहार (अनुबंधित संकाय सदस्य) द्वारा एफपीओ की अवधारणा एवं कृषकों के लिए एफपीओ का महत्व विषय पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही एफपीओ एवं बी-पैक्स के आपसी सह-संबंध, कार्यक्षेत्र तथा सहयोग की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। दिन का समापन प्रश्नोत्तर एवं चर्चा सत्र के साथ हुआ।

द्वितीय दिवस प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME) रहा।

श्री दीपक माथुर, जिला रिसोर्स पर्सन (इंदौर, धार, उज्जैन) द्वारा योजना के उद्देश्य, पात्रता, अनुदान प्रक्रिया, एफपीओ की भूमिका तथा लाभार्थी चयन प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। इसके अतिरिक्तश्री श्री कुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा केन्द्रीय सहकारिता नीति एवं मध्यप्रदेश सहकारिता नीति पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया।श्री योगेश नामदेव, सीबीबीओ आईटी विशेषज्ञ द्वारा एफपीओ प्रबंधन लागत (FPO Management Cost)विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई।

तृतीय दिवस एफपीओ द्वारा संधारित की जाने वाली लेखा पुस्तकों, वित्तीय अनुशासन एवं वैधानिक प्रावधानों पर केंद्रित रहा। श्री राबिन सक्सेना, सीबीबीओ लेखा एवं विधि विशेषज्ञ तथा श्री अभय गोखले द्वारा एफपीओ की लेखा प्रणाली, ऑडिट, अनुपालन एवं रिकॉर्ड संधारण की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही श्री योगेश नामदेव, सीबीबीओ आईटी विशेषज्ञ द्वारा एफपीओ केरिपोर्टिंग सिस्टम एवं डिजिटल प्रक्रियाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

चतुर्थ एवं अंतिम दिवस में केन्द्रीय क्षेत्र की 10,000 एफपीओ गठन योजना, अनुदान आवेदन प्रक्रिया, सदस्य मोबिलाइजेशन, एफपीओ इक्विटी कॉस्ट, फाइल संधारण, वैल्यू एडिशन एवं मार्केटिंग तथा निदेशक मंडल की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए गए।

श्री संतोष येड़े, सोशल मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट एवं श्री सुभाषानंद तिवारी, वैल्यू एडिशन एवं मार्केटिंग एक्सपर्ट द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्टएवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही श्री राहुल कुशवाह द्वारा एनसीडीसी (NCDC) की एफपीओ योजनाओं एवं उपलब्ध वित्त पोषण सहायता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत मेंसमापन परीक्षा, लिखित एवं मौखिक फीडबैक सत्र आयोजित किया गया। तत्पश्चात सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

समापन अवसर परश्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल, श्रीमती मीनाक्षी बान, सहित सभी सीबीबीओ डोमेन विशेषज्ञ उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम एफपीओ को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने, किसानों को संगठित कर बाजार से जोड़ने तथा "सहकार से समृद्धि" के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी संसाधन व्यक्तियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

उज्जैन में गांधी शिल्प बाज़ार का समापन

उज्जैन, कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रायोजन तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के आयोजन में गांधी शिल्प बाज़ार का आयोजन उज्जैन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह शिल्प मेला 15 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक अभिनंदन परिसर, देवास रोड, उज्जैन में आयोजित किया गया। गांधी शिल्प बाज़ार का शुभारंभ नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर श्री प्रिंस कुमार (HPO), हस्तशिल्प सेवा केन्द्र इंदौर, श्री किशन सिंह भटोल (पूर्व अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक), श्री दिलीप मरमट (सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर), श्री संजीव शर्मा (ऑडिट ऑफिसर, सहकारिता विभाग, उज्जैन), श्री सुमेर सिंह सोलंकी (प्रबंधक, जिला सहकारी संघ, उज्जैन), श्री मनीष सिंह, श्री माखन सिंह एवं श्री अवतार सिंह (मेला प्रभारी) सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहेमेले के दौरान अधिकारियों एवं अतिथियों द्वारा गांधी शिल्प बाज़ार का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों द्वारा स्वयं निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री सीधे हस्तशिल्पियों द्वारा की गई, जिसे नगरवासियों का भरपूर समर्थन मिला। गांधी शिल्प बाज़ार में भदोही के विश्व प्रसिद्ध कारपेट, भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ एवं सूट, उज्जैन की बटिक प्रिंट, दिल्ली की आकर्षक ज्वेलरी, भोपाल की जरी-जरदोज़ी एवं जूट उत्पाद, ग्वालियर व जबलपुर का पैच वर्क एवं स्टोन क्राफ्ट, हैदराबाद की कलमकारी, कोटा (राजस्थान) का हैंड ब्लॉक प्रिंट, चंदेरी की साड़ियाँ, महोबा (उत्तर प्रदेश) का आर्ट मेटल, जयपुर का लेदर वर्क, पश्चिम बंगाल की जामदानी सिल्क साड़ियाँ, पंजाब की फुलकारी, बुधनी के लकड़ी के खिलौने सहित अनेक आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेमेले को नागरिकों का उत्साहजनक प्रतिसाद प्राप्त हुआ, जिससे शिल्पकारों को विपणन का सशक्त मंच मिला तथा उनकी आय में वृद्धि हुई। आयोजन के समापन अवसर पर आयोजकों ने उज्जैन की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से भारतीय हस्तशिल्प परंपरा को संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहनमिलता है।

राजधानी भोपाल में गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ

एक छत के नीचे देशभर की हस्तशिल्प परंपराओं का अद्भुत संगम

भोपाल। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सीएचसीडीएस (CHCDS) परियोजनातथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सहकारी संघ भवन परिसर में आयोजित गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री विजय चन्द्रा, सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज एवं रजिस्ट्रार, नेशनल अकादमी (मुख्य अतिथि) द्वारा किया गया। इस अवसर परश्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने समारोह की अध्यक्षता की।

विशिष्ट अतिथियों में श्री दिलीप कुमार, एचपीओ, नागपुर, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, राज्य सहकारी संघ, भोपाल, श्री नरेश कुमार, एचएससी, भोपाल, श्री संतोष येड़े सहित अनेक गणमान्य अतिथि, अधिकारी, कारीगर एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

देशभर के हस्तशिल्पों की एक ही मंच पर प्रदर्शनी

गांधी शिल्प बाजार में भारत के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों द्वारा निर्मित पारंपरिक एवं उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। प्रमुख उत्पादों में—

- भदोही का विश्वप्रसिद्ध कालीन (कारपेट)
- भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ एवं सूट
- उज्जैन की बाटिक प्रिंट
- भोपाल की जरी-जरदोजी एवं जूट उत्पाद
- ग्वालियर एवं जबलपुर का पेचवर्क एवं स्टोन क्राफ्ट
- हैदराबाद की कलमकारी
- कोटा (राजस्थान) का हैंड ब्लॉक प्रिंट
- चंदेरी की प्रसिद्ध साड़ियाँ
- महोबा (उत्तर प्रदेश) का आर्ट मेटल
- जयपुर का लेदर वर्क
- पश्चिम बंगाल की जामदानी सिल्क साड़ियाँ
- पंजाब की फुलकारी
- बुंदेलखंड के लकड़ी के पारंपरिक खिलौने

सहित अनेक आकर्षक स्वदेशी हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।

कारीगरों को मिला सीधा बाजार, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता- इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि गांधी शिल्प बाजार कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का सशक्त मंच प्रदान करता है। इससे पारंपरिक हस्तशिल्पों के संरक्षण के साथ-साथ कारीगरों की आय में भी वृद्धि हो रही है।

गांधी शिल्प बाजार आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा, जहाँ वे एक ही स्थान पर देशभर की समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को देखने एवं खरीदने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यह आयोजन"स्वदेशी अपनाएं, कारीगरों को सशक्त बनाएं"की भावना को साकार करता है।

प्रदेश में 77वाँ गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया - झलकियाँ

भोपाल। मध्यप्रदेश में 77वाँ गणतंत्र दिवस प्रदेशभर में हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल से लेकर संभाग, जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर तक सहकारिता विभाग, किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा जेल विभाग सहित विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।